POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 मार्च, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार बजट ने अपने अमृत काल के दौरान एक समावेशी भारत की नींव रखी है, जिसमें न्यायपरस्ता, समानता के साथ विकास के उद्देश्यों को संतुलित किए जाने का प्रयास किया गया है।

बजट में गरीबों और वंचितों का खास ध्यान रखते हुए उनके लिए तत्काल जरूरतों, मसलन मुफ्त अनाज, रहने को घरों का निर्माण, सस्ता इलाज, कौशल विकास व रोजगार सृजन एवं सभी अंत्योदय परिवारों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूंजीगत व्यय की अनिवार्यता को संतुलित किया गया है।

बजट में खासतौर पर बुनियादी ढांचे को अधिक विकसित करने, कृषि को उद्यमिता से जोड़ने, पूरे देश में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने, बच्चों एवं युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एवं 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, युवा शक्ति द्वारा किए गए अनुसंधान व नवाचारों के बल पर देश की अर्थव्यवस्था को नए पंख लगाने जैसे उठाए गए कदम सराहनीय है।

माना जा रहा है, बजट में विकास का जो नया खाका सामने रखा गया है, यह देश को आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की दूरगामी सोच है, जो आगे जाकर एक 'मील का पत्थर' साबित होगी। मेरा मानना रहा है, बजट घोषणाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कृषि और किसानों के हक में उठाया बड़ा कदम

वित्तमंत्री ने बजट में खेती और किसानों से संबंधित योजनाओं के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 'कृषि त्वरक कोष' की स्थापना सराहनीय कदम है। बजट में मोटे अनाजों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की पहल भी की गई है। प्राकृतिक खेती पर खास जोर दिया गया है। तीन साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। गोबरधन योजना से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, इससे किसान व पशुपालक लाभान्वित होंगे। खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए 'पीएम प्रणाम' योजना शुरू की गई है। बजट में 20 लाख करोड़ रुपए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण देने का लक्ष्य है।

बजट में 10,787 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए, करीब 2,200 करोड़ रुपए बागवानी की उपज बढ़ाने, 60 हजार करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च करने जैसे कई प्रावधान हैं। 20 लाख करोड़ तक किसानों को ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे कृषि से संबंधित कई नए रोजगार स्थापित होंगे, किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं उपलब्ध कराने और कृषि को उद्यमता से जोड़ने के भी खास प्रावधान बजट में किए गए हैं, जिनसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। देश में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जा रहे हैं। यह सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिससे किसानों का जुडाव सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है।

जन स्वास्थ्य को अहमियत, अनुसंधान पर दिया जोर

बजट में जन स्वास्थ्य के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछले बजट की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है। देशभर में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इससे सभी राज्यों को फायदा मिलेगा। निकलसेल व एनिमिया जैसी बीमारियों का खात्मा करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा है। बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 36,785 करोड़ रुपए एवं 7,200 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए प्रावधान किया गया है। करीब 3,080 करोड़ रुपए एड्स व यौन रोग नियंत्रण पर खर्च होंगे। कोविड-19 से मुकाबले के लिए टीके पर 220 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 517 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

बजट में फार्मास्युटिकल में अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर खास ध्यान दिया गया है। इसके लिए 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए 136 करोड़ रुपए रखे गए थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार होने से गरीबों को इलाज में सहुलियत होगी। आदिवासी क्षेत्रों में सस्ता इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंच सकेंगी।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2022

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 41 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कितनी लाभकारी?'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2022 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

<u>प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2023 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।</u>

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

आधुनिक शिक्षा से होगी नींव मजबूत

केंद्र सरकार के बजट में स्कूली शिक्षा व साक्षरता के लिए 68,804.85 करोड़ रुपए तथा उच्च शिक्षा के लिए 44,094.62 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछले बजट में डिजिटल शिक्षा को खास अहमियत दी गई थी। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। इस बार बजट में बच्चों व युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने की घोषणा सराहनीय है। शिक्षार्थी इस लाइब्रेरी तक पहुंच पाएं, इसके लिए पंचायत व वार्ड स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भी बजट में है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में मोबाइल एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए सौ लैब्स बनाने की भी घोषणा की गई है।

इससे शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों की गुणवत्तापूर्ण किताबें आसानी से मिल सकेंगी। शिक्षण संस्थानों में भी संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ नए-नए पाठ्यक्रमों को पढ़ने का भी अवसर मिल सकेगा।

एमएसएमई उद्योगों को मिला सपोर्ट

आम बजट में वाणिज्य एवं उद्योग जगत के लिए 48,169 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को पूंजी का अतिरिक्त सपोर्ट मिलने से काफी राहत मिली है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के रूप में 9,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा उन्हें ताकत देगी। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल-फ्री गारंटीड ऋण दिए जा सकेंगे। घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 915 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

घाटे से जुझते स्टार्टअप्स को भी सहायता के साथ आयकर में भी छूट दी गई है। कृषि स्टार्टअप्स के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। खाद्य प्रस्करण उद्योग के लिए 1530 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए 90 हजार करोड़ रुपए का निवेश तय किया गया है। छोटी बड़ी सभी इंडस्ट्रीज तथा व्यापार क्षेत्र को अच्छा बढ़ावा देने का प्रयास है। इससे देश विकास की नई उड़ान तय करेगा और आत्मनिर्भरता की राह खुलेगी।

कौशल योजना से खुलेंगे रोजगार के द्वार

आम बजट में कौशल विकास मंत्रालय के लिए 3,517.31 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इस बार युवाओं को कौशल विकास योजना के माध्यम से सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर जुटाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, उद्योग में साझेदारी और नए उद्योगों की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाएगा। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर राज्यों में खुलेंगे। इनमें विदेशों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके अलावा 47 लाख युवाओं को अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाइपैण्ड दिए जाने का भी प्रस्ताव है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,800 पदों पर शिक्षक व सहायक कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शायद, वित्तमंत्री का मानना है कि युवाओं को अलग-अलग तरीकों से ढेरों नौकरियां मिलेंगी। पिछले बजट में ही अकेले मेक इन इंडिया के तहत अगले 5 सालों में 60 लाख और आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था।

आधारभूत ढांचे से सुधरेगी आर्थिक सेहत

इस बार बजट में आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, सौर व पवन ऊर्जा संबंधी उपक्रमों आदि का बजटीय आवंटन 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे गरीबों व जरूरतमंदों के लिए आवास बनाने पर 79 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

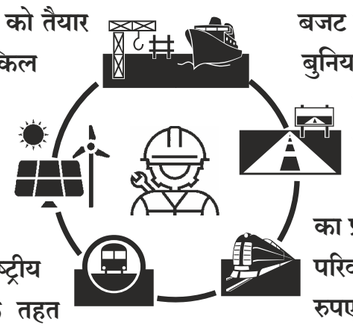

बजट में ग्रामीण और छोटे शहरों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की ओर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। शहरी विकास के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान बजट में है। सार्वजनिक परिवहन में सुधार पर 75 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। यातायात को सुगम बनाने के मकसद से गति शक्ति योजना को अमल में लाया जाएगा। इससे सड़क, रेल एवं हवाई परिवहन को खास पहचान मिलेगी। मानना है कि परिवहन सेवाओं को अधिक विकसित करने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा। स्वच्छता, पर्यावरण और अक्षय ऊर्जा तंत्र की मजबूती के लिए भी कई काम होंगे। हर घर नल से जल योजना के माध्यम से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023

जैसा कि विदित है 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना' रखा गया है।

आज ऊर्जा (बिजली) का उपभोग हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी बन गया है, लेकिन इसके बढ़ते उपभोग और उत्पादन हमारे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ जलवायु पर भी बहुत ही हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। यह एक वैश्विक चुनौती बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए एक मात्र समाधान लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

अतः सभी उपभोक्ता संस्थाएं इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

बजट में है सभी को साधने की कोशिश

मोदी सरकार ने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपए तक थी। वेतनभोगी कर्मचारी 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले सकते है। (इस बारे में टैक्स सलाहकारों से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं)

महिलाएं महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं। उन्हें इस पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। इससे टैक्स बचाने में मदद मिलेगी और ब्याज के तौर पर निश्चित आय होती रहेगी।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी 2024 तक हर महीने उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल मिलता रहेगा।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता और रोजगार के लिए सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद, सस्ता लोन और कच्चे माल के साथ बड़ा बाजार मुहैया कराएगी। बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के जरिए पारम्परिक शिल्पकारों और कारीगरों का भी ध्यान रखा गया है। इनके अलावा बजट में विभिन्न वर्गों के लिए भी अनेक घोषणाएं हैं, अगर ये सब सही रूप से धरातल पर उतरती है तो निश्चित रूप से लाभ होगा।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर